ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

12 November 2024

कृषि-खाद्य प्रणालियों की 1.3 ट्रिलियन डॉलर की छिपी लागत

सन्दर्भ: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की नवीनतम रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 में यह बताया गया है कि भारत की कृषि-खाद्य प्रणालियों की छिपी हुई लागत सालाना कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। यह लागत मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न के कारण उत्पन्न होती है। इन लागतों में स्वास्थ्य जोखिम, पर्यावरणीय क्षति और सामाजिक असमानता शामिल हैं। छिपी हुई लागतों के मामले में भारत, चीन ($1.8 ट्रिलियन) और संयुक्त राज्य अमेरिका ($1.4 ट्रिलियन) के बाद तीसरे स्थान पर है।

छिपी हुई लागतें (Hidden Cost) क्या हैं?

- **परिभाषा:** छिपी हुई लागत वह नकारात्मक लागत हैं जोकि किसी गतिविधि या प्रणाली के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो बाजार की कीमतों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होती। इनमें शामिल हैं:
  - **स्वास्थ्य लागत:** आहार संबंधी बीमारियों (जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह) के कारण होने वाले खर्च।
  - **पर्यावरणीय लागत:** खाद्य उत्पादन से होने वाली क्षति, जैसे भूमि क्षरण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जल प्रदूषण।
- ये लागतें उपभोक्ताओं द्वारा सीधे नहीं, बल्कि समाज द्वारा स्वास्थ्य देखभाल खर्च, उत्पादकता हानि और पर्यावरणीय क्षति के रूप में उठाई जाती हैं।

भारत की छिपी लागतों के प्रमुख कारक

- **आहार संबंधी जोखिम और अस्वास्थ्यकर पैटर्न:**
  - प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, शर्करा, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा के अधिक सेवन से गैर-संचारी रोग (एनसीडी) उत्पन्न होते हैं।
  - ये बीमारियाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर एक बड़ा बोझ डालती हैं और छिपी लागतों में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।
- **अस्वास्थ्यकारी आहार:**
  - प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अत्यधिक उपभोग: $128 बिलियन प्रति वर्ष (2020 क्रय शक्ति समता का उपयोग करते हुए)।
  - सम्पूर्ण वनस्पति खाद्य पदार्थों और लाभकारी वसा का कम उपभोग: $846 बिलियन प्रति वर्ष, जो फलों, सब्जियों और ओमेगा-3 वसा के अपर्याप्त सेवन से जुड़ा है।
- **पर्यावरणीय लागत:**
  - उर्वरक उपयोग और औद्योगिक खाद्य उत्पादन प्रथाओं के परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नाइट्रोजन अपवाह और भूमि क्षरण।
  - खाद्य और उर्वरक उत्पादन से होने वाले उत्सर्जन, छिपी लागतों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

वैश्विक आंकड़ों की तुलना में भारत की छिपी लागत:

- **चीन:** $1.8 ट्रिलियन
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** $1.4 ट्रिलियन
- **भारत:** $1.3 ट्रिलियन
- **वैश्विक छिपी लागतें:** वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों की कुल छिपी लागतें प्रतिवर्ष लगभग $12 ट्रिलियन हैं, जिनमें से 70% लागतें अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न से जुड़ी हैं।

नीति और कार्रवाई के लिए सिफारिशें:

छिपी लागतों को कम करने के लिए, एफएओ रिपोर्ट कई प्रमुख कार्यों की सिफारिश करती है:

- **मूल्य-संचालित परिवर्तन:** कृषि खाद्य प्रणालियों को अधिक टिकाऊ, समावेशी और कुशल बनाने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसके तहत, खाद्य प्रणालियों के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को समग्र रूप से समझते हुए, वास्तविक लागत लेखांकन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- **टिकाऊ प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन:** टिकाऊ खाद्य उत्पादन पद्धतियों को अपनाने के लिए वित्तीय और विनियामक प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, जैसे उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और संसाधनों का संरक्षण करना।
- **स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना:** पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए नीतियाँ लागू करनी चाहिए। संभावित उपायों में शामिल हैं:
  - स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए सब्सिडी।
  - शर्करायुक्त, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर कर।
  - पौधे-आधारित आहार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान।

विश्व का पहला CO2-से-मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र

संदर्भ: हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने मध्य प्रदेश स्थित विंध्याचल पावर प्लांट में विश्व के पहले CO2-से-मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन किया। यह परियोजना कार्बन प्रबंधन और टिकाऊ ईंधन उत्पादन में उपलब्धि है, जोकि जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित ऊर्जा समाधानों की ओर बढ़ने में एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

कार्बन कैप्चर और ईंधन उत्पादन में वैश्विक स्तर पर प्रथम उपलब्धि

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- विंध्याचल में इस नवीन संयंत्र को फ्लू गैसों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) को संग्रहित करने और इसे मेथनॉल (मूल्यवान ईंधन और औद्योगिक रसायन) में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।: इस प्रक्रिया में प्रमुख घटक शामिल हैं:
  - » **CO_2 कैप्चर:** यह संयंत्र विंध्याचल पावर प्लांट की फ्लू गैसों से प्रतिदिन 20 टन CO_2 को कैप्चर करता है। यह संयंत्र 4.8 गीगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली स्टेशन है।
  - » **हाइड्रोजन उत्पादन:** प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से पानी से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, जो इस रूपांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
  - » **मेथनॉल संश्लेषण:** कैप्चर की गई CO_2 को हाइड्रोजन के साथ संयोजित कर प्रतिदिन 10 टन मेथनॉल का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग परिवहन, औद्योगिक एवं रासायनिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में स्थायी ईंधन स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

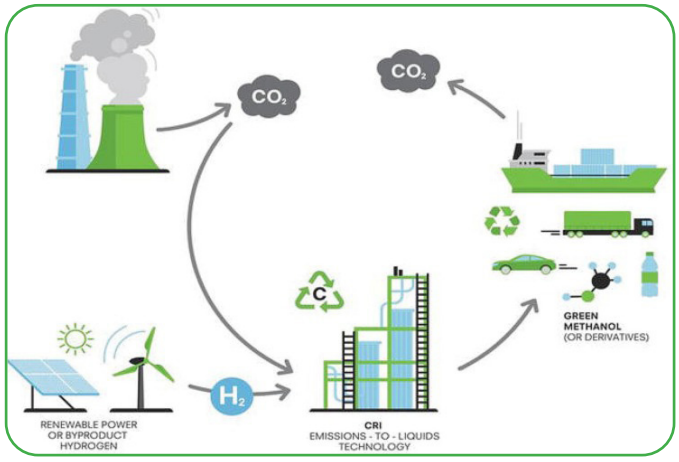

एनटीपीसी का भारत की शुद्ध–शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान :

- एनटीपीसी की CO2-से-मेथनॉल रूपांतरण पहल पेरिस समझौते के तहत भारत के व्यापक जलवायु लक्ष्यों और 2070 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की प्राप्ति की महत्वाकांक्षा के साथ संरेखित है। एक प्रमुख बिजली उत्पादक के रूप में, एनटीपीसी भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह परियोजना हरित प्रौद्योगिकी और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के क्षेत्र में कंपनी के नेतृत्व को प्रदर्शित करती है।

एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में:

- एनटीपीसी लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। 7 नवंबर, 1975 को स्थापित, एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी बन गई है और यह देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह पर्यावरणीय स्थिरता को संबोधित करते हुए भारत के समग्र विकास के लिए विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने के मिशन के साथ काम करती है।

भारत के ऊर्जा परिवर्तन में एनटीपीसी की भूमिका:

- एनटीपीसी का प्रमुख फोकस स्थिरता और सतत ऊर्जा समाधान पर है। कंपनी ने CO2-से-मेथनॉल संयंत्र के अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसके तहत 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किए हैं, जोकि भारत की ऊर्जा संरचना को स्वच्छ, टिकाऊ और विविध बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने पर पहला वैश्विक सम्मेलन

सन्दर्भ: हाल ही में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने हेतु पहला वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 7-8 नवम्बर, 2024 को बोगोटा, कोलंबिया में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के साथ होने वाले व्यापक दुर्व्यवहार से निपटना था। सम्मेलन में इस चिंताजनक आंकड़े पर ध्यान केंद्रित किया गया कि लगभग 1 बिलियन बच्चे, जोकि कुल बच्चों का लगभग आधे हैं, हर वर्ष शारीरिक, मानसिक या यौन दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं।

सम्मेलन की मेजबानी:

- कोलंबिया और स्वीडन की सरकारों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से इस कार्यक्रम की मेजबानी की। इसमें शामिल थे:
  - » विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
  - » यूनिसेफ
  - » बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के विशेष प्रतिनिधि

सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य:

- **राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवित करना:** इंस्पायर और पाथफाइंडिंग पहल जैसे ढाँचों के माध्यम से बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करना।
- **बच्चों/युवाओं के नेतृत्व में आंदोलन:** बाल हिंसा को रोकने

के लिए जागरूकता बढ़ाने और नीतियों की वकालत करने के लिए बच्चों/युवाओं के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू करना।

- **राजनीतिक घोषणापत्र अपनाना:** राजनीतिक घोषणापत्र को अपनाना, जिससे सरकारों को बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने और उसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध किया जा सके।

व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग की पेशकश

सन्दर्भ: हाल ही में विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान प्रभाग के संयुक्त सचिव श्री जे.पी. सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब और अन्य वरिष्ठ अफगान नेताओं के साथ बैठक की।

बैठक के मुख्य विवरण:

- **चाबहार बंदरगाह का प्रस्ताव:**
  - » भारत ने अफगान व्यवसायों को चाबहार बंदरगाह तक पहुँच प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो ईरान में स्थित एक रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गहरे पानी वाला बंदरगाह है, जिसका विकास और संचालन भारत द्वारा किया जाता है।
  - » चाबहार बंदरगाह भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है, जिससे अफगानिस्तान की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ती है और आयात-निर्यात की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।
- **मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित:**
  - » तालिबान द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, भारत की ओर से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता जारी रखी जाएगी।
  - » भारत ने लगातार अफगान लोगों को गेहूं, दवाइयाँ और चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई है।

भारत का कूटनीतिक रुख:

- भारत तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता है, जिसने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया था। हालांकि, भारत ने काबुल में एक कार्यात्मक राजनयिक उपस्थिति बनाए रखी है।
- भारत का दूतावास अब भी कार्यरत है और मानवीय प्रयासों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए जून 2022 से एक तकनीकी टीम वहाँ तैनात है।

चाबहार बंदरगाह का महत्व:

- सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की रणनीति का प्रमुख केंद्र है।
- 500 मिलियन डॉलर के निवेश से विकसित चाबहार, अफगानिस्तान को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए समुद्र तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
- यह अफगानिस्तान के खनिज, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध:

- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - » भारत ने 1980 के दशक में सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य अफगानिस्तान को मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे।
  - » 1990 के दशक में अफगान गृह युद्ध और तालिबान सरकार के दौरान भारत के संबंध कमजोर हो गए थे।
- **2001 के बाद के घटनाक्रम:**
  - » अफगानिस्तान पर अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद, भारत ने नवगठित लोकतांत्रिक सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और इसके बाद के वर्षों में अफगानिस्तान को सहायता और पुनर्निर्माण में मदद की

भारत–अफगानिस्तान संबंधों में हालिया घटनाक्रम:

- **दूतावास पुनः खोला गया:** 2022 में, भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला, जिसे अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद बंद कर दिया गया था।

- **मानवीय सहायता:** भारत ने अपने मानवीय प्रयास जारी रखे हैं और संकट के दौरान अफगानिस्तान की मदद के लिए 500,000 कोविड वैक्सीन खुराक और 2,500 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया है।
- **बुनियादी ढांचा विकास:** भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें सलमा डैम और अफगान संसद भवन जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत और अफगानिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और दोनों देशों के बीच माल के सुचारू परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए दो हवाई गलियारे स्थापित किए हैं, जिससे आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिला है।

पॉवर पैक्ड न्यूज़

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

- हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की और न्यायमूर्ति खन्ना को आधिकारिक रूप से पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लिया, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक विशिष्ट कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को अपना कार्यकाल समाप्त कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना छह महीने की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे।
- न्यायमूर्ति खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। इनकी न्यायिक यात्रा 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के साथ आगे बढ़ी, जहां 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।
- जनवरी 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने अपनी वर्तमान नियुक्ति तक कार्य किया।

झुरोंग रोवर

- चीन के तियानवेन-1 मिशन के अंतर्गत झुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर अरबों वर्ष पहले महासागर के अस्तित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
- झुरोंग रोवर 2021 में मंगल के यूटोपिया प्लैनिटिया क्षेत्र में उतरा और उसने तलछटी चैनल, गर्त और मिट्टी के ज्वालामुखी जैसी भूवैज्ञानिक विशेषताओं का पता लगाया, जोकि मंगल पर एक प्राचीन समुद्र तट की उपस्थिति का संकेत देते हैं। नासा के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर से प्राप्त आंकड़ों के साथ इस खोज का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि लगभग 3.68 अरब वर्ष पहले मंगल पर एक महासागर मौजूद था, जोकि समय के साथ जम गया।
- यह अध्ययन मंगल ग्रह पर समुद्री वातावरण में हुए परिवर्तनों का समर्थन करता है और इस संभावना को बढ़ाता है कि वहां सूक्ष्मजीवी जीवन रहा हो।
- माना जाता है कि लगभग 3.42 अरब वर्ष पूर्व यह महासागर लुप्त हो गया, क्योंकि मंगल एक रहने योग्य ग्रह से ठंडी और शुष्क ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया।
- यह खोज मंगल के जल इतिहास और पूर्व जीवन की संभावनाओं पर नई जानकारी देती है और इस प्रश्न को गहराई से जांचने की आवश्यकता पर बल देती है कि मंगल के पानी का क्या हुआ। अन्य अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि ग्रह की सतह के नीचे अब भी तरल पानी के बड़े भंडार हो सकते हैं।

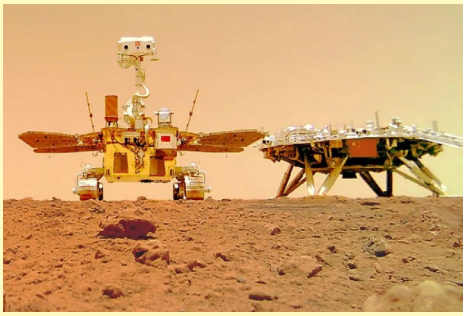

शिव नादर हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2024 में शीर्ष पर

- हाल ही में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर ने 2,153 करोड़ रुपये के उल्लेखनीय दान के साथ हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूची भारत के सबसे उदार परोपकारी लोगों को मान्यता देती है। इसमें मुकेश अंबानी और उनका परिवार 407 करोड़ रुपये के योगदान के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि बजाज परिवार 352 करोड़ रुपये का दान करके तीसरे स्थान पर है।

- सूची में नए शामिल हुए कृष्णा चिवुकुला ने 228 करोड़ रुपये के दान के साथ सबसे उदार व्यक्ति के रूप में पहचान बनाई है। अडानी समूह 330 करोड़ रुपये के परोपकारी योगदान के साथ शीर्ष पांच में शामिल है।
- महिला परोपकारियों में रोहिणी नीलेकणी 154 करोड़ रुपये के दान के साथ शीर्ष 10 में सबसे आगे हैं। जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ सबसे कम उम्र के परोपकारी हैं, जिन्होंने रेनमैटर फाउंडेशन को 120 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।
- हुरुन इंडिया परोपकार सूची सामाजिक कल्याण के लिए कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत योगदान की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है तथा भारत की चुनौतियों से निपटने में परोपकार की भूमिका को रेखांकित करती है।

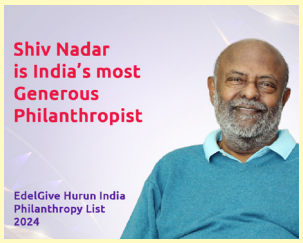

गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति वाला भारत का पहला राज्य बना

- गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027 की शुरुआत के साथ एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस नीति का उद्देश्य गुजरात को सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता में अग्रणी बनाना और इस क्षेत्र में प्रगति को प्रोत्साहित करना है।
- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साणंद में माइक्रोन के उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, मार्क और पैक (एटीएमपी) संयंत्र की आधारशिला रखी।
- पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (पीएसएमसी) के सहयोग से धोलेरा के श्सेमीकॉन सिटीश में भारत की पहली एआई-सक्षम सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित की जा रही है।
- नीति में प्रमुख प्रोत्साहन शामिल हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर 100% एकमुश्त रिफंड, 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी और 12 रुपये प्रति घन मीटर पानी की दर। भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में परिकल्पित धोलेरा में सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए 75% भूमि अधिग्रहण सब्सिडी प्रदान की जा रही है।